निबंधन संख्या पी0टी0-40

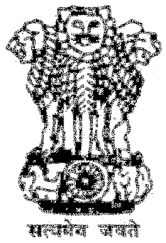

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 25 पटना, बुधवार, 2 आषाढ़, 1932 (श0) / 23 जून, 2010 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	5-6
पूरक	---
पूरक-क	7-18

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

10 जून 2010

संख्या–6/प्रो0–6–03/2008–2581/वा0क0––बिहार वित्त सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों के द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–6/प्रो0–6–03/2008–1742/वा0 क0, दिनांक 5 मई 2008 के आलोक में वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त कोटि से वाणिज्य–कर उपायुक्त कोटि में स्वीकृत पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप, दिनांक 5 मई 2008 के पूर्वाह्न में प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण किया गया, जिसे अस्वीकृत करते हुए दिनांक 5 मई 2008 के अपराह्न के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है:–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान	वर्ष 2007 का मूल वरीयता क्रमांक
1	श्री अरूण कुमार वर्मा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, अंकेक्षण, पटना	72
2	डॉ0 विनोद कुमार दुदानी, वाणिज्य–कर उपायुक्त, प्रभारी, बेगुसराय अंचल, बेगुसराय।	73
3	श्री राजकुमार, वाणिज्य–कर उपायुक्त, बिहार, पटना	76
4	श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य–कर उपायुक्त, प्रभारी, सारण अंचल, छपरा।	79
5	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, वाणिज्य–कर उपायुक्त (अंकेक्षण), गया	80
6	श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।	81
7	श्री ओम प्रकाश झा, वाणिज्य–कर उपायुक्त, प्रभारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर।	82
8	श्री छोटेलाल बैठा, वाणिज्य–कर उपायुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर	94
9	श्री सुरेश प्रसाद, वाणिज्य–कर उपायुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर	134

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 शमीम, अवर सचिव।

16 जून 2010

सं० 6/अ0–3–13/2007–2673/वा0क0––श्री चंदन कुमार, वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), मधेपुरा अंचल, मधेपुरा को उनकी पुत्री की शादी हेतु दिनांक 16 जून 2010 से 15 जुलाई 2010 तक मुख्यालय से बाहर रहकर उपार्जित अवकाश, उपभोग करने की अनुमति दी जाती है।

2. श्री कुमार की अवकाश अवधि के लिए श्री राजेशपति त्रिपाठी, वाणिज्य–कर पदाधिकारी, मधेपुरा अंचल मधेपुरा को वाणिज्य–कर पदाधिकारी (प्रभारी), मधेपुरा अंचल मधेपुरा के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 शमीम, अवर सचिव।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
28 मई 2010

सं० 1/स्था0–सां0–12–03/08–2937—विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 4 मई 2010 के लिए गए निर्णय के आलोक में श्री राठौर यशोवर्द्धन, सांख्यिकी सहायक, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को आदेश निर्गत की तिथि से सांख्यिकी पदाधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान 5500–175–9000 एवं पुनरीक्षित वेतनमान पी0वी0–2–9300–34800 + ग्रेड पे0–4200 रू0) के पद पर नियमित प्रोन्नति देते हुए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में पदस्थापित किया जाता है ।

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन चौधरी, अवर सचिव ।

योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना
14 मई 2010

सं० यो01/1–120/94–**1693**/यो0वि0—गृह(विशेष) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 4575 दिनांक 7 अप्रील 2010 के क्रम में पारस्परिक स्थानान्तरण होने के कारण श्री जयदीप कुमार एक्का, जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद को दिनांक 1 जून 2010 के पूर्वाह्न से झारखंड राज्य के लिए विरमित किया जाता है ।

2. पारस्परिक स्थानान्तरण में यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

3. गृह(विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 277, दिनांक 3 फरवरी 2009 के आलोक में वरीयता निर्धारण होगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कमलेश्वर गिरि, अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

Office of the Superintendent PMCH

TENDER

No. 213—Vide Govt. of Bihar, Health Department letter no 45(1) dated 27th January 2010 the Bihar State Blood Bank, Patna Medical College Hospital, Patna 800 004, Bihar invites sealed tender for disposal of:

1. Human Fresh Frozen Plasma (FFP)
2. Human Cryo-Poor Plasma. (CPP)

Terms and conditions are as follows:

1. NOC from Drugs Controller India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, New Delhi for collecting excess unused Plasma (FFP & CPP) from licensed blood banks.
2. NOC from Drugs Controller India, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, New Delhi for fractionation of Plasma in India or for exporting for fractionation.
3. Cost of packing, transportation (Cold Chain) to be borne by the purchaser.
4. The company in whose favor the bid will be made should deposit Rs. One lac in the form of demand draft in favor of Bihar State Blood Bank, PMCH, Patna in advance, as guarantee money.
5. A Memorandum of understanding (MOU) to this effect will be signed.
6. The rate will be valid till 31st March 2011.
7. Technical and Financial bid to be submitted in separate envelops super subscribed "TECHNICAL BID" and "FINANCIAL BID" respectively.
8. Tender should be typed, not hand written. Any cutting should be initialed.
9. Bid will be accepted only by speed post or registered post, and not by courier.
10. Last date for submission is 30th June 2010
11. Bids received after last date will not be considered.
12. Any dispute will be resolved in Patna jurisdiction.

13. Superintendent, Patna Medical College Hospital, Patna may cancel the tender, without any reason.
14. Website www.prdbihar.org & www.pmch .in may be visited for details.

Place:- Patna Sd/-Illegible
Date :-28th May 2010 Superintendent,

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Suresh Prasad, S/o Late Satya Narayan Prsad, Village-Sauli, P.S.- Bakunthpur, District - Gopalganj while holding District Co-operative Officer-cum-Assistant Registrar, West Champaran, Motihari office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 104/2008 dated 1st December 2008

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Suresh Prasad who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-03/10 -3598]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Om Prakash Singh, S/o Late Jagdip Singh, Pramila Villa, Lalji Tola, P.S. - Gandhi Maidan, District - Patna, Permanent Address - Village - Chatrauli, P.S.-Dhanarua, District - Patna while holding Inspector weights and measurement, Raxaual, District - Motihari office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 71/2009 dated 22nd June 2009

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Om Prakash Singh who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-04/10 -3599]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Kalika Prasad Sinha, I.A.S. (Retired), S/o Late Ram Bhajan Sinha, Road No. 23, Sri Krishna Nagar, Patna while holding Vice-Chairman, Patna Regional Development Authority office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 16/2000 dated 14th September 2000.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Kalika Prasad Sinha who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-05/10 -3600]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Shrikant Prasad, S/o Shri Dudhnath Prasad, New Alkapuri, P.S. - Gardanibagh, District - Patna, Permanent Address - Village-Niranjanpur, P.S. - Kachchwan, District - Rohtas, Bihar while holding Executive Engineer, Rural Works Division-2, Aurangabad office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 81/2009 dated 1st August 2009.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Shrikant Prasad who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-02/10 -3601]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Kapil Muni Rai, S/o Late Ram Keshwar Raj, Present - Krishi Nagar, A.G. Colony, P.S. - Shastri Nagar, District - Patna, Permanent Address - Village -Banshi Dihara, P.S.-Sahar, District-Bhojpur while holding Enforcement Sub-Inspector, Purnia office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 85/2009 dated 17th August 2009.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Kapil Muni Rai who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-13/10 -3602]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary..

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Sanjay Kumar, S/o Shri Phuldev Prasad, House No. 402, Shanti Lok Apartment, Shekhapura, Patna while holding Excise Superintendent, Muzaffarpur office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 86/2009 dated 19th August 2009.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Sanjay Kumar who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-10/10 -3603]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Bhola Prasad, S/o Shri Brahamdeo Prasad, Village - Sandalpur, P.S. - Harnaut, District - Nalanda while holding The then Divisional Forest Officer, Kaimur office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 52/2007 dated 20th April 2007.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Bhola Prasad who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-16/10 -3604]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Yogendra Kumar Singh (Retired), S/o Late Subhadayal Singh, Mohalla - Maranpur, P.S. - Civil Line, District - Gaya while holding The then Revenue Officer, Nagar Nigam, Gaya office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 82/2007 dated 10th July 2007.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Yogendra Kumar Singh who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-17/10 -3605]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Wakil Prasad Yadav, S/o Kishun Prasad Yadav, Village- Mirzapur Bausi, P.s. - Bausi, District - Banka, At present Krishna Kutir, Aviyanta Nagar, Gola Road, Jalalpur, P.S. - Phulwari Sharif, District - Patna while holding The then Sales Tax Officer Sitamarhi office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 35/2009 dated 4th April 2009.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Wakil Prasad Yadav who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-11/10 -3606]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Anil Kumar, S/o Late Ishwar Sharan Lal, House No. 54, West Boring Canal Road, Anandapuri, Patna while holding The then Assistant Commissioner, Sales Tax, Sahabad Circle, Ara office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 70/2007 dated 31st May 2007.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Anil Kumar who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-12/10 -3607]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Madan Prasad Srivastava, S/o Shri Hriday Narayan Srivastava, Flat No. 302 and 304 A, Ashirwad Apartment, Nageshwar Colony, Patna while holding Executive Engineer, NH Division, Chapra office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 89/2009 dated 31st July 2009.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Madan Prasad Srivastava who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-14/10 -3608]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 8th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Raghuvansh Kunwar, S/o Late Ram Eqbal Kunwar, Village - Taran, P.S. - Mohaddinagar, District-Samastipur, At Present House No.-50 A/1293, Gandhi Nagar, Kanti Factory Road, P.S.-Agamkuan, District Patna while holding The Then Motor Vehicle Inspector, Aurangabad office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No.: 59/2009 dated 27th May 2009.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Raghuvansh Kunwar who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-15/10 -3609]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 9th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Girish Kumar, S/o Late Sidheshwar Sharma, At Present R/o Park Road, Kadamkuan, Patna while holding The Post of Assistant, Patna Treasury, Collectorate, Patna committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No 39/2006 dated 25th July 2006.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Girish Kumar who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-18/10 -3617]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

VIGILANCE DEPARTMENT

FORM No. I
DECLARATION
The 9th June 2010
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

WHEREAS, It is alleged that Shri Naga Ram (now retired) S/o Late Mahadeo Ram, Village-Bhitbharwan, P.S. + District, Gopalganj while holding Regional Deputy Director of Education, Purnea office and also while serving in different capacities under Bihar Government committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Case No 43/2009 dated 28.04.2009.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Shri Naga Ram who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

[No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-06/10 -3618]
By the order of the Governor of Bihar,
Sd/- Illegible,
Principal Secretary.

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
15 अप्रील 2010

सं० 22 / नि0सि0(वीर0)–7–107 / 98 / 642—वित्त अंकेक्षण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रूपांकण प्रमण्डल, वीरपुर के कार्यालय का वर्ष–9 / 88 से 11 / 97 तक किए गए अंकेक्षण में छलपूर्ण निकासी का मामला प्रकाश में आने पर उक्त निकासी में रोकड़पाल के साथ सहभागिता रहने तथा बिहार फाइनेन्सियल रूल भाल्यूम–1 एवं बिहार ट्रजरी कोड के नियमों का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए श्री ब्रज किशोर सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, रूपाकंण प्रमण्डल, वीरपुर के विरूद्व सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1956 के नियम–55 के तहत संकल्प ज्ञापांक–1114 दिनांक 14 सितम्बर 2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। श्री ब्रज किशोर सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

अतएव श्री ब्रज किशोर सिन्हा को उक्त आरोपों से दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री ब्रज किशोर सिनहा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद, उप–सचिव।

---

30 अप्रील 2010

सं० 22 / नि0सि0(पू0)–1–4 / 06 / 713—श्री वैधनाथ राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, अमदाबाद, कटिहार द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में बरती निम्नांकित अनियमितताओं के लिए आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गयाः–

(1) बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में अमदाबाद प्रखण्ड के रौशना से गोविन्दपुर तक (लाभा–चौकिया– पहाड़पुर महानन्दा दायॉ तटबंध) पक्की सड़क निर्माण कार्य के मद सं0–14 (iii) एवं 14 (iv) को प्राक्कलन के अतिरिक्त मद के रूप में शामिल कर कुल रु० 3,12,104.98 हेतु गलत स्वीकृति प्राप्ति हेतु प्राक्कलन तैयार करना।

(2) स्वीकृत प्राक्कल एवं एकरारनामा में अंकित अतिरिक्त मद सं0–14 (iii) एवं 14 (iv) के विरूद्व सातवें, आठवें एवं नौवे चालू विपत्रों के माध्यम से कुल रु० 1,86,197 के गलत भुगतान हेतु विपत्रों को अनुशंसा करना।

(3) स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा के मद सं0–1 (iv) के अन्तर्गत यांत्रिक विधि से मिट्टी ढुलाई मद में मुख्य अभियन्ता से लीड प्लान स्वीकृति के बगैर प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ से लेकर आठवें चालू विपत्रों के माध्यम से कुल रु० 42,77,259 के भूगतान हेतु विपत्रों की गलत अनुशंसा करना।

(4) गोाविन्दपुर ढाला से कमरूद्वीन टोला तक तटबंध को रूपांकित फारमेंशन लेवेल पर ही मिट्टी भराई कराकर पक्का रोड का निर्माण कराना।

उपरोक्त आरोपों के लिए श्री वैघनाथ राय, सहायक अभियन्ता के विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1270 दिनांक 11 दिसम्बर 2006 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप सं0–3 एवं 4 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक–1410 दिनांक 3 दिसम्बर 2009 द्वारा श्री राय, सहायक अभियन्ता से द्वितीय कारण पृच्छा किया गयाः–

(क) निन्दन वर्ष 2004–05

(ख) असंचयात्मकक प्रभाव से चार वेतनवृद्वि पर रोक।

श्री राय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त आरोप सं0–3 प्रमाणित पाया गया एवं आरोप सं0–4 प्रमाणित नहीं पाया गया। अतः प्रमाणित आरोपों के लिए श्री वैघनाथ राय, सहायक अभियन्ता को निम्नदण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

(क) निन्दन वर्ष 2004–05

(ख) दो वेतनवृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

सरकार का उक्त निर्णय श्री वैघनाथ राय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार, अमदाबाद को संसूचित किया जाता हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद, उप–सचिव।

---

30 अप्रील 2010

सं० 22 / नि0सि0(पू0)–1–04 / 06 / 714—श्री अख्तर आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार द्वारा वर्ष 2004–05 के उक्त पदस्थापन अवधि में बरती गई अनियमितता यथा अमदाबाद प्रखण्ड के रोशना से गोविन्दपुर तक (लामा, चौकिया, पहाड़पुर, महानन्दा दायॉ तटबंध) पक्की सड़क निर्माण कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में अंकित अतिरिक्त मद सं0–14 (iii) एवं 14 (iv) के विरूद्व नौवे चालू विपत्रों द्वारा कुल रु० 1,53,822 के गलत भूगतान हेतु दोषी पाते हुए श्री आलम के विरूद्व विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1271 दिनांक 11 दिसम्बर 2006 द्वारा श्री आलम के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरानत श्री आलम के विरूद्व आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। फलस्वरूप श्री अख्तर आलम, कार्यपालक अभियन्ता को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री अख्तर आलम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार को संसूचित किया जाता हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद, उप–सचिव।

---

30 अप्रील 2010

सं० 22/नि0सि0(दर0)–16–17/08/715—श्री शंभु प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक–662 दिनांक 15 जुलाई 2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वगर्वीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री शंभु प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, दरभंगा को संसूचित किया जाता हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद, उप–सचिव।

---

4 मई 2010

सं० 22/नि0सि0(पू0)–1–01/06/725—श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, काढ़ागोाल, सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि वर्ष 2002–03 में विभागीय स्तर से गुमटी टोला लिंक बॅाध के निर्माण में बरती गई अनियमिताओं के लिए निम्नांकित आरोप गठित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गयाः–

(1) बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, काढ़ागोला अन्तर्गत वर्ष 2002–03 में विभागीय स्तर से गुमटी टोला लिंक बांध का निर्माण कराया गया। बॅाध निर्माण में कुल 19 अद्द ट्रैक्टरों को प्रयोग में लाया गया था। लेकिन उक्त 19 अदद ट्रैक्टरों का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया एवं कटिहार द्वारा कराने पर मात्र पन्द्रह अद्द ट्रैक्टरो का ही सत्यापन हो सका। अर्थात चार अद्द गलत निबंधन संख्या के विरूद्व बिना कार्य कराये ही भुगतान किया गया।

(2) सत्यापित पन्द्रह अद्द ट्रैक्टरो में से दो अद्द निबंधन संख्या स्कुटर एवं मोटर साईकिल का पाया गया।

(3) अर्थात बांध निर्माण में लाये गये उन्नीस अद्द ट्रैक्टरो में से छः ट्रैक्टरो को फर्जी दिखाकर मिट्टी ढुलाई कार्य एवं मजदूरी के रूप में कुल 12.87 लाख का संदेहास्पद भुगतान किया गया।

(4) कार्य में वित्तिय अनुशासन की कमी पाया जाना एवं बोगस कार्य का भुगतान कर विभाग को आर्थिक क्षति पहुचाना।

उक्त आरोपों के लिए श्री सिंह के विरूद्व विभागीय संकल्प 352 दिनांक 5 अप्रील 2006 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 बी0 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभागीय कार्यवाही में जॅाच पदाधिकारी से प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त जॅाच प्रतिवेदन से निम्नांकित विन्दुओं पर असहमति व्यक्त की गईः–

(1) चार अद्द ट्रैक्टरो के निबंधन की जॅाच का प्रतिवेदन उपलबध नहीं होने से स्पष्ट है कि निबंधन फर्जी है।

(2) चार अद्द ट्रैक्टरो जिनका निबंधन फर्जी है, एवं दो अद्द ट्रैक्टरो की जगह निबंधन स्कुटर/मोटर साईकिल का है, के द्वारा कराये गये मिट्टी कार्य की मात्रा संदेहास्पद है एवं जिसके चलते हुए आर्थिक क्षति का भुगतान संदेहास्पद है।

(3) पर्यवेक्षण की कमी एवं अधिनस्थ पर नियंत्रण नहीं रखना जिसके चलते गलत बोगस भुगतान हुआ।

उपर्युक्त आरोपों के लिए पॅाच वर्षो तक दस प्रतिशत पेंशन पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए श्री सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता से विभागीय पत्रांक 882 दिनांक 2 सितम्बर 2009 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा में वर्णित तथ्यों संलग्न साक्ष्यों एवं संचालन पदाधिकारी के जॅाच प्रतिवेदन के आलोक में पुरे मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त किसी तरह की वित्तिय अनियमितता का आरोप नहीं पाया गया। फलतः श्री सिंह जो कि 31 जनवरी 2005 को सेवानिवृत हो चुके है को दोषमुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, काढ़ागोला सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद, उप–सचिव।

14 मई 2010

सं० 22/नि0सि0(देव0)–10–01/2008/766—श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, लधु जल संसाधन विभाग, बिहार जब उक्त प्रमण्डल में पदस्थापित थें तब दिनांक 25.9.07 को अजय बराज सिकटिया झारखण्ड के जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार वर्षा होने एवं बराज के सभी गेट बन्द रहने के फलस्वरूप नहर पॉच स्थलों पर टूट गया जिससे लगभग 50.00 लाख रूपये की क्षति हुई। झारखण्ड सरकार द्वारा जॉचोपरान्त उक्त क्षति के लिए श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया को दोषी पाया गया। श्री सिंह का कैडर विभाजन के उपरान्त बिहार राज्य कैडर आवंटित होने के फलस्वरूप झारखण्ड सरकार द्वारा उक्त मामले से संबंधित अभिलेख की छाया प्रति जल संसाधन विभाग, बिहार को प्राप्त कराते हुए श्री सिंह को निलंबित कर उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गयां

जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखं की समीक्षा बिहार सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्व उक्त वर्णित आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया गया। प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए इनके विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया।

उक्त वर्णित स्थिति में श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है

(1) श्री सिंह का निलंबन अवधि में मुख्यालय मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण संगठन का कार्यालय अनीसाबाद, पटना निर्धारित किया जाता है।

(2) निलंबन अवधि में श्री सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(3) श्री सिंह के विरुद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबंधी आदेश/संकल्प अलग से निर्गत की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद, उप–सचिव।

---

20 मई 2010

सं० 22/नि0सि0(मुज0)–6–6/2007/786—श्री राजेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता तत्कालीन पुनर्वास पदाधिकारी, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखण्ड रून्नीसैदपुर में 10 कि0मी0 बागमती बॉध के विस्तार के क्रम में भीतर पड़ने वाले ग्रामों/टोलों में अवस्थित परिवारों एवं सरकारी संस्थानों के अग्रिम सर्वेक्षण सूची नहीं समर्पित करने के संबंध में आपसे विभागीय पत्रांक 708 दिनांक 18 जुलाई 2007 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त आपको विभाग द्वारा दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय श्री राजेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार प्रसाद, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+250-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in